SHRI SONTOSH MOHAN DEV: Sir these are in a very advance stage. Sir, full Boards would be there in almost every company before the next Session of Parliament begins.

अल्पसंख्यक आयोग/सलाहकार-समितियों का गठन

*211. **डा॰ कुमकुम राय:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा कितने राज्यों में अल्पसंख्यक आयोग/सलाहकार समिति का गठन किया गया है;

(ख) कितने राज्यों में ऐसे आयोग/समिति का गठन अब तक नहीं हुआ; और

(ग) तत्संबंधी कारण क्या हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग राज्यों में अल्पसंख्यक आयोग/सलाहकार समितियां गठित नहीं करता है। तथापि, 15 राज्यों ने राज्य अल्पसंख्यक आयोग गठित किए हैं।

(ख) 14 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों ने अभी तक राज्य अल्पसंख्यक आयोग गठित नहीं किए हैं।

(ग) राज्य अल्पसंख्यक आयोग/सलाहकार समितियों के गठन का मामला राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

Setting up of Minority Commission/Advisory Committees

†* 211. SHRIMATI KUM KUM RAI: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) the number of the States in which the Minority Commission/ Advisory Committee has been constituted/Advisory Committee has been constituted by the National Minority Commission;

†*Original notice of the question was received in Hindi.

(b) the number of the States in which such commission/committee has not been constituted so far; and

(c) the reasons therefor?

THE MINISTER OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRIMATI MEIRA KUMAR) : (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) National Minority Commission does not constitute Minority Commissions/Advisory Committees in the States. However, 15 States have constituted State Minority Commissions.

(b) 14 States and six Union Territories have not constituted the State Minority Commissions so far.

(c) The matter of setting up State Minority Commissions/Advisory Committees falls within the jurisdiction of the State Governments.

डा० कुमकुम राय: सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि 14 राज्यों और 6 केन्द्र शासित प्रदेशों में अभी तक मायनोरिटी कमीशन नहीं बने हैं। मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या देश में इन मायनोरिटी कमीशंस का सरकार की नजर में महत्व नहीं है? यदि है तो अब तक उस ने उन राज्यों में जहां कि अल्प संख्यक आयोगों का गठन नहीं हुआ है, क्या सरकार ने उन के गठन के संबंध में सलाह देने का काम किया है और उन राज्यों ने उस सलाह के एवज में क्या जवाब दिया है?

श्रीमती मीरा कुमार: सभापति जी, मैं आप के माध्यम से सम्मानित सांसद को बताना चाहूंगी कि राष्ट्रीय अल्प संख्यक आयोग का गठन एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक कानून के तहत होता है और वह गठन केवल राष्ट्रीय आयोग का होता है। जहां तक राज्यों का प्रश्न है, उन्हें अपने यहां प्रांतीय स्तर पर अल्प संख्यक आयोग के गठन के लिए स्वयं पहल करनी होती है। हम यहां से राज्यों में उन आयोगों का गठन नहीं कर सकते। इसलिए यह उन प्रांतीय सरकारों का अपना निर्णय है कि कहां पर उन्होंने गठन कर लिया है और कहां पर नहीं किया है।

श्री सभापति : क्वैश्चन नंबर 212.

श्री शाहिद सिद्दिकी : सर, यह मायनोरिटी का सवाल है ...(**व्यवधान**)...

†[شری شاہد صدیقی: سر، یہ مائناریٹی کا سوال ہے.....مداخلت.....]

†Transliteration of Urdu Script.

श्री सभापति : आप दो बार पूछ चुके हैं।

श्री शाहिद सिद्दिकी : सर, एक सप्लीमेंटरी ...(व्यवधान)...

شری شاہد صدیقی: سر، ایک سپلیمینٹری.....مداخلت.....†

श्री सभापति: एक सप्लीमेंटरी मैं allow कर रहा हूं।

श्री शाहिद सिद्दिकी: सर, समय ...(व्यवधान)...

شری شاہد صدیقی: سر، سمجھئے.....مداخلت.....†

श्री सभापति: समय है, आप को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। प्रश्न संख्या 212.

Literacy Rate

*212. SHRI S. ANBALAGAN: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the current literacy rate of the country and that of the States, State-wise;

(b) whether the country is still lagging behind many developing countries in terms of literacy rate;

(c) if so, the steps taken by Government during the last two years and those proposed to be taken to increase the literacy rate;

(d) whether it is a fact that female literacy rate is less than the male literacy rate; and

(e) if so, the details thereof, State-wise, and the steps being taken/ proposed to be taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MD. ALI ASHRAF FATMI) : (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (e) As per Census 2001, the literacy rate of the country is 64.84%. The male literacy rate is 75.26% and female literacy rate is 53.67%. A statement indicating the State-wise literacy rates of males and females is given in the Statement I (*See* below).

†Transliteration in Urdu Script.